आरबीआई की समीक्षा बैठक के फैसले पर रहेगी बाजार की नजर

मुंबई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में ज्यादा बढ़ोतरी किये जाने से वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध गहराने एवं आर्थिक मंदी की आशंका में बीते सप्ताह ढाई प्रतिशत से अधिक की गिरावट में रहे घरेलू शेयर बाजार की इस सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के निर्णय पर नजर रहेगी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की

भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता और गहराने की संभावना

शुरुआत धीमी रही है, जिसका प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा अपेक्षा से अधिक टैरिफ लगाया जाना है। इससे आईटी और धातु जैसे क्षेत्रों ने व्यापक बाजार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं और संभावित जवाबी व्यापार कदमों की आशंका को दर्शाता है। निवेशक अब वैश्विक व्यापार साझेदारों की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, जिससे भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता और गहराने की संभावना है।

इस सतर्क रुख का असर सोने और बॉन्ड जैसी निवेश के लिए सुरक्षित गंतव्य मानी जाने वाली परिसंपत्तियों की ओर बढ़ते झुकाव में भी देखा जा रहा है, जहां कीमतों में निरंतर तेजी बनी हुई है। वहीं भारत पर लगाए गए टैरिफ की दर अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम रही है, जो बाजार के लिए कुछ राहत की बात है। साथ ही निवेशकों की निगाहें आरबीआई की चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक पर भी टिकी हैं। यदि फैसला अनुकूल रहता है, तो ब्याज दर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकता है।

न्यूज ब्रीफ

संसदीय समिति की आलोचनाः जिला खनिज फाउंडेशन कोष के स्थानांतरण पर चिंता

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि देश के कई राज्यों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) कोष को खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने पर चिंता जताई है। समिति ने बताया कि कुछ राज्यों में डीएमएफ कोष का अन्यत्र इस्तेमाल हो रहा है, जो उसके मूल उद्देश्य से भिन्न है। डीएमएफ कोष का मूल उद्देश्य है खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले के लिए एक गैर-लाभकारी सांविधिक कोष होना। संसद की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में डीएमएफ कोष को निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्यत्र इस्तेमाल होने के साथ-साथ इसका हस्तांतरण राज्य के खजाने या राज्यस्तरीय कोष में किया जा रहा है, जो खनन अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन करता है। कमेटी ने इसे विफलता और कानूनी अनियमितियों के रूप में देखा है ।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को बिक्री में वृद्धि की उम्मीद, कंपनी बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने और नए मॉडल पेश करने की बना रही योजना

Toyota Kirloskar

नई दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने चालू वित्त वर्ष में भी अपनी बिक्री में वृद्धि की रफ्तार कायम रखने की उम्मीद जताई है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की योजना है चालू वित्त वर्ष में अपने बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने और नए मॉडलों की पेशकश करने की। वाधवा ने बताया कि कंपनी अपने एसयूवी और एमपीवी वाहनों की मांग मजबूत रखने की उम्मीद रख रही है। उन्होंने इस बारे में कहा कि कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कार्बन निरपेक्षता के मामले में अपनी प्रतिबद्धता के तहत विद्युतीकरण की संभावना देख रही है। उन्होंने यह भी जताया कि कंपनी स्थिति मजबूत करने और वाहन बाजार में अधिक भूमिका निभाने के लिए बढ़े हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अपनी उपस्थिति का विस्तार भी करना चाहती है। अधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा निर्यात में भी अच्छी वृद्धि देखी जा रही है और उनकी योजना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात को और भी बढ़ावा दें। टीकेएम ने जारी किया यह बड़ा लक्ष्य और उनकी योजनाओं में तेजी और भरोसा देखा जा रहा है।

ट्रंप के टैरिफ का असर, जेएलआर ने रोका अमेरिका को कारों का निर्यात

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है और इसके साथ ही अप्रैल में कारों पर 25 फीसदी टैरिफ भी लागू हो गया है। इस फैसले के चलते जगुआर लैंड रोवर ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अमेरिका को कारों का निर्यात रोक दिया है। जगुआर लैंड रोवर के प्रवक्ता ने बताया कि वे अमेरिकी बाजार में नई ट्रेडिंग टर्म की दिशा में काम कर रहे हैं और ब्रिटेन में बदलाव को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए कारों का निर्यात रोक दिया है। जगुआर लैंड रोवर के ग्राहकों के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह कंपनी ब्रिटिश प्लांट से अमेरिका में अपनी गाड़ियां निर्यात करती थी। ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने साल 2008 में फोर्ड मोटर्स से जेएलआर का खरीदा था और इसके बाद से जगुआर लैंड रोवर की व्यापक मौजूदगी अमेरिकी बाजार में बढ़ती रही थी। उसके प्रवक्ता ने कहा, जगुआर लैंड रोवर के लक्जरी ब्रांडों के लिए अमेरिका एक उत्कृष्ट मार्केट है, और हम अपनी नई ट्रेडिंग टर्म को एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी उद्यमिता को बनाए रख सकें। इस बदलाव के चलते जगुआर लैंड रोवर ने अप्रैल में निर्यात खेप रोकने का फैसला लिया है, जो कि कंपनी के लिए एक व्यापक और महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि उसके लक्जरी ब्रांडों की ग्लोबल अपील है और वह बदलती बाजार स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है।

बीते सप्ताह तेल-तिलहनों में गिरावट, मूंगफली, सरसों के भाव बढ़े

कारोबारी धारणा बिगड़ने की वजह से सभी तेल-तिलहनों के दाम में गिरावट देखी गई

नई दिल्ली

बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतें कम होने तथा 'शुल्क युद्ध' की बढ़ती आशंकाओं के बीच कारोबारी धारणा बिगड़ने की वजह से सभी तेल-तिलहनों के दाम में गिरावट देखी गई और सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल के दाम नुकसान के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि इससे पिछले सप्ताह जिस कच्चे पामतेल (सीपीओ) का दाम 1,200-1,205 डॉलर प्रति टन था, वह समीक्षाधीन सप्ताह में घटकर 1,160-1,165 डॉलर प्रति टन रह गया।

बाजार धारणा बिगड़ने का यह मुख्य कारण रहा। हालांकि, यह दाम जो पहले सोयाबीन से लगभग 100 डॉलर अधिक था वह अब घटने के बाद सोयाबीन से लगभग 60 डॉलर अधिक ही है। हालांकि, जितना पाम, पामोलीन तेल का दाम टूटा है, उतनी गिरावट सोयाबीन में नहीं आई। बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 75 रुपये की गिरावट के साथ 6,200-6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का थोक भाव 450 रुपये की गिरावट के साथ 13,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 40-40 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 2,340-2,440 रुपये और 2,340-2,465 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमशः 25-25 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 4,400-4,450 रुपये और 4,100-4,150 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी तरह सोयाबीन दिल्ली एवं सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम के दाम क्रमशः 425 रुपये, 325 रुपये और 225 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 13,400 रुपये, 13,150 रुपये और 9,550 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए।स मीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तिलहन का भाव 150 रुपये की गिरावट के साथ 5,700-6,075 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं मूंगफली तेल गुजरात और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल का भाव क्रमशः 450 रुपये और 55 रुपये की गिरावट के साथ 14,200 रुपये और 2,235-2,535 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ। कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का दाम 350 रुपये की गिरावट के साथ 12,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली का भाव 400 रुपये की गिरावट के साथ 14,100 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 350 रुपये की गिरावट के साथ 13,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। गिरावट के आम रुख के अनुरूप समीक्षाधीन सप्ताह में बिनौला तेल 375 रुपये की गिरावट के साथ 13,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

सिक्किमः भारत का एकमात्र राज्य जिसे नहीं देना होता कोई टैक्स

नई दिल्ली

भारत में इनकम टैक्स का मोर्चा हमेशा चर्चा का विषय रहता है। लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां नागरिकों को कोई टैक्स नहीं देना होता है। यह इसलिए है क्योंकि इस राज्य में लागू किए गए खास कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति को भारत सरकार को आयकर नहीं देना होता है। सिक्किम को 1975 में भारत में विलय किया गया था और वादा किया था कि इस राज्य के पुराने कानून और विशेष दर्जे बरकरार रहेंगे। जिसे 1948 का सिक्किम आयकर मैनुअल सुनिश्चित करता है।

इस नियम के अनुसार, सिक्किम के रहने वाले सभी नागरिकों को टैक्स मुक्ति प्राप्त है। वर्ष 2008 में सिक्किम के लिए केन्द्रीय बजट में एक विशेष अनुमान शामिल किया गया जिसने राज्य के 94 फीसदी से अधिक लोगों को आयकर से छूट दी। इसके अलावा, सिक्किम के व्यक्तियों को शेयरों पर डिविडेंड और अर्जित आय पर भी छूट प्राप्त होती है। सिक्किम का यह विशेष दर्जा यहां के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। आम व्यक्ति इस सिक्किमी निवासी सुविधा का अच्छे से अच्छे विकल्पों के साथ लाभ उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में सिक्किम के कर कानून निरस्त कर दिए गए।

35 हजार रुपये तक सस्ती मिल रही मारुति ईको

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की ईको कार इस महीने खास ऑफर के तहत 35,000 रुपये तक सस्ती मिल रही है। कंपनी इस पर 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस दे रही है। यह ऑफर 30 अप्रैल 2025 तक ही मान्य है। ईको की एक्स-शोरूम कीमतें फिलहाल 5.44 लाख से 6.70 लाख रुपये तक हैं। हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि मई से कार की कीमतों में 62,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में यह ऑफर कार खरीदने वालों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। ईको में 1.2-लीटर के सीरीज इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल पर 80.76 पीएस की पावर और 104.5 एनएम टॉर्क देता है। सीएनजी वेरिएंट में यह घटकर 71.65 पीएस और 95 एनएम हो जाता है।

एक लीटर पेट्रोल में 73 किमी का माइलेज देती है हीरो बाइक

अगर आप ऑफिस आने-जाने के लिए फ्यूल एफिशिएंट बाइक की तलाश में हैं, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। हीरो मोटोकॉर्प की इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 83,571 रुपए है। आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जोड़ने पर इसकी ऑन-रोड कीमत राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यह फिर भी 84,000 रुपए से कम में आ सकती है। हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक है और कंपनी का दावा है कि यह बाइक अराई सर्टिफिकेशन के अनुसार एक लीटर पेट्रोल में 73 किलोमीटर का माइलेज देती है। यानी फुल टैंक पर यह बाइक लगभग 715 किलोमीटर तक चल सकती है। हालांकि, असली माइलेज सड़क की स्थिति और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। इस बाइक में 97.2 सीसी का 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ अच्छी ईंधन दक्षता भी देता है।

टेस्ला के आने से बढ़ेगा भारत में ईवी बाजार, प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित नहीं: बीएमडब्ल्यू

कंपनी के अधिकरी ने कहा, भारत में दो ब्रांड बीएमडब्ल्यू और मिनी के तहत कुल 1,249 इलेक्ट्रिक कार बेच चुके हैं

नई दिल्ली

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा है कि वह भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में टेस्ला के आने की संभावना को लेकर चिंतित नहीं है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि टेस्ला के आने से इस खंड को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा के समूह भारत में दो ब्रांड बीएमडब्ल्यू और मिनी के तहत कुल 1,249 इलेक्ट्रिक कार बेच चुका है। 2025 की पहली तिमाही में कंपनी पहले ही 646 इकाइयां बेच चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत में अपनी कुल बिक्री में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के जरिये हासिल करने का अनुमान लगाया है। मुझे लगता है कि बाजार बढ़ना चाहिए। जब भी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, तो हमने देखा है कि बाजार बढ़ता है। उनसे पूछा गया था कि टेस्ला के भारत में प्रवेश करने के साथ ईवी बाजार कैसे आकार लेगा और इसपर बीएमडब्ल्यू का क्या रुख रहेगा। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता से प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी बाजारों में, हम साथ-साथ मौजूद हैं। आप पिछले साल दुनियाभर के आंकड़े देख सकते हैं, हम ही हैं जो आगे बढ़ रहे थे। वैश्विक स्तर पर हमारी ईवी की बिक्री बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक विनिर्माता इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में वृद्धि के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2024 में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने कुल 4,26,594 पूर्ण-इलेक्ट्रिक वाहन बेचे और ईवी की बिक्री में उसने 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।

राजस्थान में रीको 533 औद्योगिक भूखंडों का करेगा आवंटन, 7 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

जयपुर

राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल विकास एवं निवेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) ने राजस्थान में पूंजी निवेश करने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक समूहों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। राजस्थान सरकार के तहत रीको इस माह 533 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करेगा। इन भूखंडों का आवंटन करने की प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू होगी और ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल, 2025 तक रखी गई है। रीको ने एक बड़े पूल के माध्यम से 103 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया था, जिससे उसे 353 करोड़ रुपए की आय हुई थी। अब, आवंटन हो रहे इन भूखंडों की बिक्री से रीको को करोड़ों रुपए की राजस्व आय होने की संभावना है।

इन भूखंडों का आवंटन किया जाने वाला है वे काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास को एक नई ऊँचाई देंगे। आवंटन की गई इन 533 औद्योगिक भूखंडों में

आबूरोड़, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, बोरानाड़ा, दौसा, घिलौठ, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, मंडोर, और नीमराना शहरों में समाहित है। इसके अलावा, बालोतरा, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, राजसमंद, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉट्स भी उपलब्ध हैं।

रिको की टर्म लोन स्कीम के तहत, निवेशक भूमि की लागत का 75 फीसदी राशि का ऋण ले सकेंगे, जिसके लिए उन्हें 8.5 फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा। कुल राशि का 25 फीसदपी जमा करने के बाद, उन्हें शेष राशि का भुगतान 11 किस्तों में किया जा सकेगा। इसके साथ ही, रीको नॉन इंडस्ट्रियल प्लॉट की आवंटन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

अमेरिका के टैरिफ से पाकिस्तान परेशान, दो समितियां गठित की, प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन जाएगा ताकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा हो सके

इस्लामाबाद । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ निर्देश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए दो समितियों की गठन की घोषणा की है। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पष्टीकरण दिया है। पहली स्टीयरिंग कमेटी में वित्त मंत्री आगे बढ़ेंगे, जो कि मंत्री, व्यापारी नेता, सचिव और शिक्षाविद मिलकर रहेंगे। दूसरी वर्किंग ग्रुप का नेतावाणी वाणिज्य सचिव करेंगे। अंत में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन जाएगा ताकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा हो सके। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अनुसार, उनके अमेरिका से कुल निर्यात 5.44 बिलियन डॉलर रहा है। वित्त मंत्री ने मैक्रोइकॉनॉमिक्स स्टेबिलिटी हासिल करने के बारे में भी चर्चा की है और उत्पादकता आधारित विकास की जरूरत को जताया है। आम जनता को भी ध्यान में रखते हुए मंत्री ने बताया कि मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास चल रहा है, जिससे आम आदमी को भी फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि टैरिफ के निर्णय के बाद, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।